गजराज

बनाम

दिल्ली राज्य (एनसीटी)।

(आपराधिक अपील संख्या 2272, 2010)

सितम्बर 22, 2011

[आर.एम.लोढ़ा और जगदीश सिंह खेहर, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860: धारा 302 हत्या का दोषसिद्धि - पीड़ित का शव एक घर में मिला। उसका मोबाइल फोन, लाइसेंसी रिवॉल्वर और 3 लाख रुपये गायब थे। जांच से पता चला कि पीड़ित के मोबाइल हैंडसेट का आई.एम.ई.आई. कथित हत्या के तुरंत बाद आरोपी के सिम नंबर का उपयोग किया गया था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया, जिसे उच्च न्यायालय ने अपील पर बरकरार रखा। माना: अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस अकाट्य तथ्य पर आधारित थे कि प्रत्येक मोबाइल हैंडसेट में एक विशेष आई.एम.ई.आई. नंबर होता है। जब भी किसी मोबाइल हैंडसेट का उपयोग कॉल करने के लिए किया जाता है, तो कॉल करने वाले और कॉल करने वाले व्यक्ति का नंबर रिकॉर्ड करने के अलावा, उपयोग किए गए हैंडसेट के IMEI नंबर भी सेवा प्रदाता द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं। साक्ष्य रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि जिस तारीख को पीड़ित की हत्या की गई थी, उस दिन उसका सिम

नंबर बंद हो गया था। उसके मोबाइल हैंडसेट के इस्तेमाल से ही पुलिस ने आरोपी का पता लगाया। हत्या की घटना के तुरंत बाद पीड़ित के मोबाइल हैंडसेट का उपयोग जिस पर आरोपी ने अपने पंजीकृत फोन से काॅल किया था, आरोपी की पहचान का वैध आधार था। घटना के समय पीड़ित के साथ आरोपी का सम्बंध उक्त सिम/ आई.एम.ई.आई. विवरण से पूरी तरह से प्रमाणित हुई। आरोपी के पास से पीड़ित की रिवॉल्वर भी बरामद हुई। अभियोजन आरोप साबित करने में सफल रहा। दोषसिद्धि कायम रही । इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (आई.एम.ई.आई.)

टेली- संचार: अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई)। आईएमईआई की सहायता से आरोपी की पहचान।

साक्ष्य: साक्ष्य में इनकार- आरोपी के पास से रिवॉल्वर और पीड़ित का मोबाइल बरामद किया गया - रिकवरी मेमो पर आरोपी के भाई और पिता के हस्ताक्षर- आरोपी के भाई ने रिकवरी मेमो पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। उसने दावा किया कि उसके हस्ताक्षर खाली कागज लिए गए थे, जिनका उपयोग रिकवरी मेमो तैयार करने में किया गया था। इसी तरह का बयान आरोपी के पिता ने भी दिया है: यह स्पष्ट है कि आरोपी का भाई और पिता आरोपी को बरी कराने के लिए प्रयास करेंगे। इसके बावजूद न आरोपी के भाई और न ही पिता ने रिकवरी मेमो पर उनके हस्ताक्षरों की सत्यता पर विवाद किया - इसलिए, यह स्पष्ट था कि

रिकवरी मेमो पर उनके हस्ताक्षर प्रामाणिक थे। यदि जांच एजेंसी द्वारा आरोपी के भाई और उसके पिता के हस्ताक्षर जबरन ले लिये जाते तो न केवल आरोपी बल्कि उसके भाई और उसके पिता भी हंगामा खड़ा कर देते और सम्बंधित अधिकारियों को इंगित करते हुए अभ्यावेदन देते कि पुलिस ने कोरे कागज पर उनके हस्ताक्षर लिये थे। उनके बयानों से उनके द्वारा की गई ऐसी किसी भी कार्रवाई का पता नहीं चला। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने रिकवरी मेमो पर विधिवत अपने हस्ताक्षर किए थे, जिसके द्वारा आरोपी की निशानदेही पर मृतक की रिवॉल्वर, साथ ही पीड़ित का मोबाइल हैंडसेट बरामद किया गया था। दंड संहिता, 1860- एस. 302.

अभियोजन पक्ष का मामला था कि दिल्ली के एक घर में एक शव मिला था। जांच करने पर पता चला कि शव पीडब्लू-23 के पति का था। मृतक की पत्नी का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने बताया कि जब उसका पति चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकला था, तो उसके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, मोबाइल फोन SIM (9871879824) और 3 लाख रुपये भी थे, जिसे वह समझौता करने के लिये दिल्ली ले गया था। जांच के दौरान पुलिस यह पता लगाने में सक्षम थी कि मोबाइल(9871879824) का उपयोग मृतक के आईएमईआई नंबर 35136304044030 वाले मोबाइल हैंडसेट पर किया गया था। आगे की जांच से पता चला कि उक्त IMEI का उपयोग पीड़ित- मृतक की हत्या के तुरंत बाद आरोपी- अपीलकर्ता के मोबाइल फोन सिम 9818480558 के लिए किया गया था। इससे पुलिस

को अपीलकर्ता को पकड़ने और तीन मोबाइल हैंडसेट बरामद करने में मदद मिली, जिनमें से एक का IMEI नंबर 35136304044030 था। पुलिस ने अपीलार्थी के पास से मृतक की लाइसेंसी रिवाल्वर भी बरामद कर ली। 3 लाख रुपये की रकम तो नहीं मिली, लेकिन हत्या के दो दिन बाद अपीलकर्ता के खाते में 9000 रुपये की जमा प्रविष्टि हुई थी।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 और 404 के तहत दोषी ठहराया और उसे धारा 302, आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास और 50000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 404 के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीन साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये का भुगतान करने की भी सजा सुनाई गई। हालाँकि, उसे आईपीसी की धारा 380 और 452 के तहत उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, हालांकि, सजा को संशोधित किया, क्योंकि आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, उच्च न्यायालय ने कारावास की अवधि तीन साल से घटनाकर छः महीने कर दी।

तत्काल अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसे कथित तौर पर

IMEI नंबर 35136304044030 वाला मोबाइल हैंडसेट रखने के आधार पर फंसाया गया था; उक्त IMEI नंबर वाला उक्त मोबाइल हैंडसेट, मृतक की पत्नी (PW23) के खुलासे पर पुलिस द्वारा खोजा गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में इस तरह का प्रक्षेपण अपीलकर्ता को फंसाने के लिये झूठी कहानी गढने के लिये था। पीडब्लू23 के साक्ष्य में विसंगति थी, जिसने ट्रायल कोर्ट के समक्ष गवाही देते हुए कहा था कि उसके पति ने उसे दोपहर लगभग 12 बजे और उसके बाद लगभग 3 बजे फोन किया था; कॉल विवरण से पता चला कि PW23 द्वारा बताए गए समय के आसपास, चंडीगढ़ टेलीफोन से दो इनकमिंग कॉल प्राप्त हुई थी और PW23 के बयान के अनुसार, यह मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9871879824 से आउटगोइंग कॉल होनी चाहिए थी(जैसा कि मृतक की पत्नी ने दावा किया था कि उसके पति को दो काॅल आई थी), फिर भी कॉल रिकॉर्ड के अनुसार, ये इनकमिंग कॉल थीं; इस विसंगति के आधार पर, अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि मृतक के मोबाइल फोन (सिम) से अपीलकर्ता का पता लगाने का तथ्य जांच एजेंसी के हाथों पूरी तरह से मनगढ़ंत था; यह भी सुझाव देने की मांग की गई थी कि यदि जांच एजेंसी का अपीलकर्ता तक पहुंचने का सिद्धांत मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9871879824 के कॉल डिटेल्स पर आधारित था, तो यह अस्वीकार्य था; यह अनुमान लगाना स्वाभाविक था कि पुलिस फोन नंबर (9871879824) की कॉल डिटेल के आधार पर अपीलकर्ता तक नहीं पहुंच सकती थी और

इसलिए, उसके कब्जे से रिवॉल्वर और मोबाइल हैंडसेट (मृतक के स्वामित्व वाला) की बरामदगी का सवाल ही नहीं उठता और उन्हें अपीलकर्ता को फंसाने के लिए उस पर प्लांट किया गया होगा।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना कि 1.1. हालाँकि जहाँ तक PW23 के बयान का सवाल है, आरोपी- अपीलकर्ता द्वारा उसके द्वारा उल्लिखित विसंगति को इंगित करना पूरी तरह से उचित था, फिर भी जिस तरह से अपीलकर्ता की पहचान की गई और उसका पता लगाया गया, (जांच के दौरान) अभियोजन मामले की सत्यता को पूरी तरह से स्थापित किया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एक अकाट्य तथ्य पर आधारित थे, अर्थात्, प्रत्येक मोबाइल हैंडसेट में एक होता है। किसी भी दो मोबाइल हैंडसेट का IMEI नंबर एक जैसा नहीं होता। और जब भी किसी मोबाइल हैंडसेट का उपयोग कॉल करने के लिए किया जाता है, तो कॉल करने वाले और कॉल करने वाले व्यक्ति का नंबर रिकॉर्ड करने के अलावा, उपयोग किए गए हैंडसेट के IMEI नंबर भी सेवा प्रदाता द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं। अभियोजन साक्ष्य की जांच करते समय उक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जांच की प्रक्रिया में पहला कदम PW23 से जानकारी प्राप्त करना था कि मृतक मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9871879824 का उपयोग कर रहा था। रिकॉर्ड पर साक्ष्य से संकेत मिलता है कि उक्त सिम नंबर 23.7.2005 को बंद हो

गया, यानी, जिस तारीख को मृतक की हत्या हुई थी। जांच की प्रक्रिया में यह सामने आया कि IMEI नंबर 35136304044030 वाले मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल मोबाइल फोन (सिम) नंबर (9818480558) के साथ किया गया था। यह हत्या के तुरंत बाद 23.7.2005 को ही हुआ था. 2.8.2005 तक एक ही हैंडसेट से कॉल करने के लिए एक ही सिम का उपयोग किया गया था। PW22, नोडल अधिकारी, भारती एयरटेल लिमिटेड के बयान के माध्यम से, यह स्थापित हुआ कि मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9818480558 आरोपी- अपीलकर्ता के नाम पर पंजीकृत था। IMEI नंबर 35136304044030 वाले मोबाइल हैंडसेट के उपयोग से पुलिस आरोपी-अपीलकर्ता का पता लगाने में सफल रही। IMEI नंबर 35136304044030 वाले मोबाइल हैंडसेट का उपयोग, जिस पर आरोपी- अपीलकर्ता ने मृतक की हत्या की घटना के तुरंत बाद अपने पंजीकृत मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9818480558 से कॉल किया था, आरोपी की पहचान के लिए एक वैध आधार था। -अपीलार्थी. आरोपी- अपीलकर्ता को 6.8.2005 को गिरफ्तार किया गया था। घटना के समय मृतक के साथ आरोपी-अपीलकर्ता का सम्बंध उक्त सिम/ आईएमईआई विवरण से पूरी तरह से प्रमाणित हुई। मामले के उक्त अर्थ में, PW23 के बयान में विसंगति महत्वहीन हो गई। जांच के दौरान जिस प्रक्रिया से आरोपी- अपीलकर्ता की पहचान की गई, वह वैध और अप्राप्य थी। आईएमईआई हैंडसेट का नंबर, जिस पर आरोपी- अपीलकर्ता अपने नाम पर पंजीकृत मोबाइल फोन (सिम)

का उपयोग करके कॉल कर रहा था, निर्णायक प्रकृति का साक्ष्य होने के कारण, छोटी- मोटी विसंगतियों के आधार पर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः मौखिक साक्ष्य में गंभीर विसंगति के लिए भी उक्त वैज्ञानिक साक्ष्य के आगे झुकना पड़ता। [पैरा 10] [713- ई- एच; 714- ए- एच; 715- ए- बी]

1.2. कथित तौर पर रिवॉल्वर और मोबाइल हैंडसेट आरोपी- अपीलकर्ता की निशानदेही पर बरामद किए गए थे। पीडब्लू12, अपीलकर्ता के भाई ने रिकवरी मेमो पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। उसने दावा किया कि उनके हस्ताक्षर कोरे कागजों पर लिए गए थे, जिनका उपयोग रिकवरी मेमो तैयार करने में किया गया था। इसी तरह का बयान अपीलकर्ता के पिता पीडब्लू13 ने भी दिया था। यह स्पष्ट है कि PW12 और PW13 ने आरोपी- अपीलकर्ता को बरी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। इसके बावजूद न तो पीडब्लू12 और न ही पीडब्लू13 ने रिकवरी मेमो पर उनके हस्ताक्षरों की सत्यता पर विवाद किया। इसलिए, यह स्पष्ट था कि रिकवरी मेमो पर उनके हस्ताक्षर प्रामाणिक थे। यदि जांच एजेंसी द्वारा आरोपी- अपीलकर्ता के भाई और पिता के हस्ताक्षर जबरन ले लिए गए होते, तो न केवल आरोपी- अपीलकर्ता बल्कि उसके भाई पीडब्लू 12 और उसके पिता पीडब्लू 13 भी हंगामा खड़ा कर देते। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह बताते हुए अभ्यावेदन दिया होगा कि पुलिस ने कोरे कागजों पर उनके हस्ताक्षर लिए थे। पीडब्लू12 और पीडब्लू13 के बयानों से

उनके हाथों ऐसी किसी कार्रवाई का पता नहीं चला। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने रिकवरी मेमो पर विधिवत अपने हस्ताक्षर किए थे, जिसके द्वारा मृतक की रिवॉल्वर, साथ ही, आईईएमआई नंबर 35136304044030 वाला पैनासोनिक का मोबाइल हैंडसेट आरोपी-अपीलकर्ता की निशानदेही पर बरामद किया गया था। इसे देखते हुए आरोपी- अपीलार्थी की ओर से पेश की गई दूसरी दलील में भी कोई दम नहीं है। [पैरा 11,12] [715- डी- ई; जी- एच; 716- ए- डी]

1.3. आरोपी ए द्वारा अपने बैंक खाते में जमा की गई कुल 3 लाख रुपये की राशि में से 9,000/- रुपये की राशि यह स्थापित करने के लिए उचित आधार नहीं हो सकती है कि कथित अपराध आरोपी- अपीलकर्ता द्वारा किया गया था। लेकिन फिर, अपराध को स्थापित करने में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए भारी सबूतों को ध्यान में रखते हुए अर्थात् आरोपी- अपीलकर्ता से जीवित और इस्तेमाल किए गए कारतूस के साथ मृतक की रिवॉल्वर की बरामदगी, आईएमईआई 35136304044030 नंबर वाले पैनासोनिक के मोबाइल हैंडसेट की आरोपी-अपीलकर्ता के कब्जे से बरामदगी और तथ्य यह है कि आरोपी- अपीलकर्ता मृतक की हत्या के तुरंत बाद मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9818480558 के साथ इसका उपयोग कर रहा था जो आरोपी- अपीलकर्ता के नाम पर पंजीकृत था (और वह अपनी गिरफ्तारी तक इसका उपयोग करता रहा), किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है, कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी-

अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के साथ- साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी स्थापित किए गए आरोपों को साबित किया है। [पैरा 14] [717- ए- डी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2272/ 2010 ।

दिल्ली उच्च न्यायालय के 2008 की आपराधिक अपील संख्या 461 द्वारा अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 18.03.2009 से उत्पन्न।

अपीलकर्ता की ओर से संजय के. अग्रवाल।

जे.एस.अटरी, पी.के. दे और संधना संधू (अनिल कटियार के लिये) प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

जगदीश सिंह खेहर, जे. 1. तथ्य, जैसा कि वे 2005 के सत्र मामले संख्या 68 में कड़कड़डूमा में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से उभरते हैं, जोकि दिनांक 21.4.2008 को निर्णीत किया गया। आपराधिक अपील संख्या 461/2008 में दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला, जिसका निर्णय दिनांक 18.3.2009 को हुआ, और इस दौरान गवाहों के बयानों की जांच की गई। यहां अभियुक्त- अपीलकर्ता के अभियोजन (जो हमें अतिरिक्त दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं) से पता चलता है कि 23.7.2005 को शाम लगभग 6.25 बजे, पुलिस स्टेशन कृष्णा नगर में एक टेलीफोन कॉल प्राप्त हुई, जिसमें जानकारी दी गई कि दिल्ली के कृष्णा

नगर के मकान नंबर F-9/33 में एक लाश पड़ी थी. उपरोक्त टेलीफोन प्राप्त होने पर. कॉल, डेली डायरी नंबर 31ए पुलिस स्टेशन कृष्णा नगर में दर्ज की गई थी। पुलिस अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर तैनात किया गया। पूछताछ करने पर यह निष्कर्ष निकला कि शव मकान नंबर 303, गगन विहार, दिल्ली निवासी हरीश कुमार का था। मृतक हरीश कुमार को कनपटी के बाईं ओर और पेट के बाईं ओर भी गोली लगी थी। तदनुसार, दिनांक 7.1.2006 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 452 और 380 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन कृष्णा नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 297/2005 दर्ज की गई थी। 14.12.2007 को, आरोपी- अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 404 के तहत एक अतिरिक्त आरोप भी तय किया गया था।

2. मृतक की पत्नी मिनाक्षी, जो चंडीगढ़ में थी, उसके पति हरिश कुमार(मृतक) की हत्या की सूचना मिलने पर दिल्ली पहुंची। उसने शवगृह में मृतक के शव की पहचान की। मिनाक्षी ने पुलिस को बताया कि उसका पति भी उसके साथ चंडीगढ़ में था। और जब वह चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकले तो उनके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, एक मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9871879824 और 3 लाख रुपये की रकम भी थी, जिसे वह समझौते की बातचीत के लिए दिल्ली ले गए थे।

3. जांच के दौरान, पुलिस यह पता लगाने में सक्षम थी कि मोबाइल

फोन (सिम) नंबर 9871879824 का उपयोग IEMI नंबर 35136304044030 वाले मोबाइल हैंडसेट पर किया जा रहा था। आगे की जांच में यह पाया गया कि उपरोक्त मोबाइल हैंडसेट IEMI नंबर वाला था। मृतक हरीश कुमार की हत्या के तुरंत बाद मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9818480558 के लिए नंबर 35136304044030 का उपयोग किया जा रहा था। सिम नंबर 9818480558 अभियुक्त-अपीलकर्ता के नाम से रजिस्टर्ड था। इस जांच प्रक्रिया के माध्यम से, पुलिस अंततः आरोपी-अपीलकर्ता गजराज सिंह, पुत्र वीर सिंह, निवासी 12/2, कुंदन नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली तक पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी- अपीलकर्ता के पास से तीन मोबाइल हैंडसेट बरामद किए, जिनमें से एक पैनासोनिक निर्मित था जिसका IEMI नंबर 35136304044030 था, यानी वह हैंडसेट जिसमें सिम नंबर 9871879824 मृतक द्वारा इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने आरोपी अपीलार्थी के पास से मृतक हरीश कुमार की लाइसेंसी रिवाल्वर भी बरामद कर ली। 3 लाख रुपये की पूरी और प्रभावी वसूली नहीं की गई, जिसके बारे में मिनाक्षी (मृतक हरीश कुमार की पत्नी) ने कहा था कि वह उस समय मृतक के पास थी, जब वह चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। पुलिस ने यह स्थापित करने के लिए कि आरोपी- अपीलकर्ता के पास उसकी कमाई से अधिक धनराशि थी, भारतीय स्टेट बैंक, कुंदन नगर शाखा, दिल्ली में आरोपी- अपीलकर्ता के खाते में 9,000/- रुपये की जमा राशि का हवाला दिया। उक्त जमा 25.7.2005 को किया गया था (संदर्भित

हत्या दो दिन पहले 23.7.2005 को की गई थी)

4. आरोपों को सही साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 29 गवाहों को परीक्षित किया। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों पर गौर करने से पता चलता है कि आरोपी- अपीलकर्ता की सजा केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मांगी गई थी, अर्थात् हत्या की तारीख पर IEMI नंबर 35136304044030 वाले मोबाइल हैंडसेट का उपयोग (और कब्ज़ा)। 23.7.2005 को आरोपी- अपीलकर्ता द्वारा मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9818480558 (जो आरोपी- अपीलकर्ता के नाम पर पंजीकृत था) के लिए। मृतक हरीश कुमार की रिवॉल्वर की बरामदगी के साथ- साथ जिंदा और चले हुए कारतूस भी बरामद किए गए। साथ ही, भारतीय स्टेट बैंक, कुंदन नगर शाखा, दिल्ली में अभियुक्त- अपीलकर्ता के खाते में 9,000/- रुपये की जमा राशि।

5. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कड़कड़डूमा, दिल्ली ने 21.4.2008 को सत्र मामला संख्या 68/2005 का निपटारा किया। यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई कि अभियोजन भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 404 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी- अपीलकर्ता के खिलाफ अपना मामला स्थापित करने में सक्षम था। हालाँकि, आरोपी- अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 380 और 452 के तहत उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था। इसके बाद दिनांक

28.4.2008 के एक आदेश द्वारा, आरोपी- अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास और 50,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। जुर्माने का भुगतान न करने पर आरोपी- अपीलकर्ता को तीन साल की अतिरिक्त अवधि के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा)। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 404 के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीन साल के कठोर कारावास और 5,000/- रुपये का जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई गई (जुर्माना भुगतान न करने की स्थिति में, आरोपी-अपीलकर्ता को)। चार महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा)। ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उपरोक्त सजाएं एक साथ चलनी थीं।

6. ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट, आरोपी- अपीलकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2008 की आपराधिक अपील संख्या 461 दायर की। अभियुक्त- अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील 18.3.2009 को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी गई। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को संशोधित किया गया था, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त- अपीलकर्ता पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, उच्च न्यायालय ने कारावास की अवधि कम कर तीन साल से छः माह कर दी थी।

7. अभियुक्त- अपीलकर्ता ने त्वरित अपील दायर करके इस

न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है ताकि 2005 के सत्र मामले संख्या 68 (दिनांक 21.4.2008) और 2008 की आपराधिक अपील संख्या 461 (दिनांक 18.3.2009) में पारित आदेशों को चुनौती दी जा सके।)

8. सुनवाई के दौरान, आरोपी- अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तीन तर्क उठाए। उपरोक्त विवाद में से पहला उनके प्राथमिक जोर का आधार था। दलील यह थी कि आरोपी- अपीलकर्ता को कथित तौर पर IEMI नंबर 35136304044030 वाला मोबाइल हैंडसेट रखने के आधार पर फंसाया गया था। जहां तक मामले के तात्कालिक पहलू का सवाल है, आरोपी-अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दलील थी कि उक्त आईईएमआई नंबर वाला उक्त मोबाइल हैंडसेट पुलिस द्वारा मृतक हरिश कुमार की पत्नी के खुलासे पर खोजा गया था और इसलिए भी कि आरोपी- अपीलकर्ता उपरोक्त हैंडसेट पर मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9871879824 का उपयोग कर रहा था। चूंकि आरोपी- अपीलकर्ता मृतक (हरीश कुमार) के मोबाइल हैंडसेट पर उसके (गजराज सिंह) नाम से पंजीकृत मोबाइल फोन (सिम) का उपयोग कर रहा था, पुलिस उसकी पहचान सुनिश्चित करने में सक्षम थी, और उसके बाद उस तक पहुंची। विद्वान वकील का उद्देश्य, पहले तर्क को आगे बढ़ाते हुए, यह स्थापित करना था कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में तत्काल प्रक्षेपण, आरोपी- अपीलकर्ता को फंसाने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ना था। विद्वान वकील के अनुसार, अभियोजन साक्ष्य में विसंगति पहले विवाद का उद्देश्य स्थापित करेगी। जिस एकमात्र विसंगति

को इंगित करने की मांग की गई थी, वह मृतक हरीश कुमार की पत्नी मिनाक्षी के बयान पर आधारित थी। पीडब्लू23 के रूप में ट्रायल कोर्ट के सामने गवाही देते हुए मिनाक्षी ने कहा था कि उसके पति ने उसे दोपहर करीब 12 बजे और उसके बाद करीब 3 बजे फोन किया था। यह दावा करने की कोशिश की गई थी कि प्रदर्श पीडब्लू25/ डीएक्स के कॉल विवरण से पता चलता है कि मिनाक्षी पीडब्लू23 द्वारा बताए गए समय के आसपास, चंडीगढ़ टेलीफोन से दो इनकमिंग कॉल प्राप्त हुई थीं। यह इंगित किया गया था, कि PW23 के बयान के अनुसार, यह मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9871879824 से आउटगोइंग कॉल होनी चाहिए थी (जैसा कि मिनाक्षी ने दावा किया था कि उसे अपने पति से उक्त दो कॉल प्राप्त हुई थीं), फिर भी प्रदर्श PW25 के अनुसार / DX, ये इनकमिंग कॉल थे। उपरोक्त विसंगति के आधार पर, आरोपी- अपीलकर्ता के विद्वान वकील का जोरदार तर्क था कि मृतक हरीश कुमार के मोबाइल फोन (सिम) से आरोपी- अपीलकर्ता का पता लगाने का जांच एजेंसी का तथ्य पूरी तरह से मनगढ़ंत था। सुझाव देने की मांग की गई कि क्या अभियुक्त तक पहुंचने की जांच एजेंसी की थ्योरी मोबाइल फोन सिम नम्बर 9871879824 की काॅल डीटेल पर आधारित है। वही स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य हो जाता है। विद्वान वकील के अनुसार, यह अनुमान लगाना स्वाभाविक होगा कि पुलिस फोन नंबर 9871879824 की कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी- अपीलकर्ता तक नहीं पहुंच सकी होगी और इसलिए,

उसके कब्जे से रिवॉल्वर और मोबाइल हैंडसेट (मृतक हरीश कुमार के स्वामित्व में) की बरामदगी का सवाल ही नहीं उठता। यह सुझाव देने की कोशिश की गई थी कि इन्हें आरोपी- अपीलकर्ता को फंसाने के लिए लगाया गया होगा।

9. जहां तक आरोपी- अपीलकर्ता के विद्वान वकील के हाथों पेश किए गए पहले विवाद का सवाल है, विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय (दिनांक 18.3.2009) द्वारा पारित आपेक्षित आदेश में दर्शाए गए तर्क पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें अभियुक्त-अपीलकर्ता को निम्नलिखित तर्क के आधार पर घटना से जोड़ा गया है।

> "26. यह मानते हुए कि कॉल रिकॉर्ड Ex.PW-22/ A साक्ष्य देता है कि 23.7.2005 की दोपहर को मोबाइल नंबर 9871870824 पर चंडीगढ़ से दो कॉल प्राप्त हुई थीं, मृतक की पत्नी की गवाही की पुष्टि करता है जो चंडीगढ़ में रह रही थी। 23.7.2005 को बताया गया कि उसने 23.7.2005 की दोपहर में मृतक से टेलीफोन पर बात की थी, जिससे यह स्थापित होता है कि मृतक द्वारा अपनी मृत्यु की तारीख पर मोबाइल नंबर 9871879824 का उपयोग किया जा रहा था; कॉल रिकॉर्ड Ex.PW-22/ A और Ex.PW22/ B स्थापित करता है कि IEMI नंबर 350608101231170 वाला हैंडसेट,

जिस हैंडसेट का इस्तेमाल आरोपी नियमित आधार पर करता था, उसका इस्तेमाल मृतक ने 10 और 11 जुलाई, 2005 को किया था और यह स्थापित करता है कि मृतक और आरोपी एक दूसरे के संपर्क में थे; कॉल रिकॉर्ड Ex.PW-22/ B इस बात का सबूत है कि जिस हैंडसेट का उपयोग मृतक ने अपनी मृत्यु की तारीख पर किया था, वह मृतक की मृत्यु के तुरंत बाद आरोपी के कब्जे में था और यह एक मजबूत मामला है। अभियुक्त के विरुद्ध अभियोगात्मक परिस्थिति; अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम है कि मृतक द्वारा अपनी मृत्यु से पहले इस्तेमाल किया गया हैंडसेट और रिवॉल्वर जो अपराध का हथियार था, आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया था..."

आरोपी- अपीलकर्ता के विद्वान वकील का यह दावा है कि मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9871879824 के आधार पर आरोपी- अपीलकर्ता का कभी पता नहीं लगाया जा सका, क्योंकि मृतक हरीश कुमार द्वारा कभी भी उपरोक्त मोबाइल नम्बर से अभियुक्त-अपीलकर्ता को कोई काॅल नहीं किया गया था। इसी तरह, आरोपी- अपीलकर्ता द्वारा अपने मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9818480558 से मृतक हरीश कुमार को कभी कोई कॉल नहीं की गई। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च

न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य हैं, और रद्द किए जाने योग्य हैं।

10. हमने अभियुक्त- अपीलकर्ता के विद्वान वकील के हाथों दिए गए पहले तर्क पर विचारपूर्वक विचार किया है, जैसा कि पिछले दो पैराग्राफ में बताया गया है। हालाँकि, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त- अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यद्यपि हमारा मानना है कि अभियुक्त- अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उल्लिखित विसंगति को इंगित करना पूरी तरह से उचित है, जहां तक मिनाक्षी पीडब्लू23 के बयान और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क का संबंध है, जैसा कि यहां ऊपर उद्धृत किया गया है, पूरी तरह से उचित नहीं हो सकता है, फिर भी हमें इसमें कोई संदेह नहीं है, कि जिस तरह से आरोपी- अपीलकर्ता की पहचान की गई और उसका पता लगाया गया, (जांच के दौरान) अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता को पूरी तरह से स्थापित करता है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एक अकाट्य तथ्य पर आधारित है, अर्थात्, प्रत्येक मोबाइल हैंडसेट में एक विशेष IEMI नंबर होता है। किसी भी दो मोबाइल हैंडसेट का IEMI नंबर एक जैसा नहीं होता। और हर बार कॉल करने के लिए मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही कॉल करने वाले का नंबर भी रिकॉर्ड किया जाता है। कॉल करने वाले व्यक्ति, उपयोग किए गए हैंडसेट के IEMI नंबर भी सेवा प्रदाता द्वारा दर्ज किए जाते हैं।

अभियोजन साक्ष्य की जांच करते समय उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जांच की प्रक्रिया में पहला कदम मिनाक्षी (मृतक हरीश कुमार की पत्नी) से सूचना प्राप्त होना था कि मृतक मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9871879824 का उपयोग कर रहा था। रिकॉर्ड पर साक्ष्य इंगित करता है कि उपरोक्त सिम नंबर 23.7.2005 को बंद हो गया, यानी, जिस तारीख को मृतक हरीश कुमार की हत्या हुई थी। जांच की प्रक्रिया में यह सामने आया कि IEMI नंबर 35136304044030 वाले मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9818480558 के साथ किया गया था। यह हरीश कुमार की हत्या के तुरंत बाद 23.7.2005 को ही हुआ था. 2.8.2005 तक एक ही हैंडसेट से कॉल करने के लिए एक ही सिम का उपयोग किया गया था। आर.के. सिंह पी.डब्ल्यू. 22 नोडल अधिकारी भारती एयरटेल लिमिटेड के बयान के माध्यम से यह स्थापित हुआ कि मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9818480558 आरोपी- अपीलकर्ता गजराज सिंह के नाम पर पंजीकृत था। IEMI नंबर 35136304044030 वाले मोबाइल हैंडसेट के उपयोग से पुलिस आरोपी- अपीलकर्ता गजराज सिंह का पता लगाने में सफल रही। मामले का केवल यही पहलू वर्तमान विवाद के उद्देश्य से प्रासंगिक है। आईईएमआई नंबर 35136304044030 वाले मोबाइल हैंडसेट का उपयोग, जिस पर आरोपी- अपीलकर्ता ने मृतक हरीश कुमार की हत्या की घटना के तुरंत बाद अपने पंजीकृत मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9818480558 से कॉल किया था, अभियुक्त-अपीलकर्ता

की पहचान के लिए एक वैध आधार था। आरोपी- अपीलकर्ता को 6.8.2005 को गिरफ्तार किया गया था। घटना के समय आरोपी-अपीलकर्ता की मृतक के साथ सम्बंध उपरोक्त सिम/ ईएमआई विवरण से पूरी तरह से प्रमाणित होती है। मामले के उपरोक्त अर्थ में, अभियुक्त-अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इंगित मिनाक्षी पीडब्लू 23 के बयान में विसंगति, साथ ही, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में दिए गए तर्क महत्वहीन हो जाते हैं। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जांच के दौरान जिस प्रक्रिया से आरोपी- अपीलकर्ता की पहचान की गई, वह वैध और अजेय थी। हैंडसेट का IEMI नंबर, आरोपी- अपीलकर्ता अपने नाम पर पंजीकृत मोबाइल फोन (सिम) का उपयोग करके कॉल कर रहा था, एक निर्णायक प्रकृति का सबूत होने के नाते, छोटी- मोटी विसंगतियों के आधार पर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वास्तव में मौखिक साक्ष्य में गंभीर विसंगति होने पर भी उपरोक्त वैज्ञानिक साक्ष्य के आगे झुकना पड़ता। यहां ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, हम आरोपी- अपीलकर्ता के विद्वान वकील के हाथों दिए गए पहले तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

11. आरोपी- अपीलकर्ता के विद्वान वकील के सामने पेश किया गया दूसरा तर्क यह था कि रिवॉल्वर की बरामदगी और आईईएमआई नंबर 35136304044030 (मृतक हरीश कुमार का) मोबाइल हैंडसेट की बरामदगी से जुड़े केवल दो स्वतंत्र गवाह थे।, अर्थात्, युवराज पीडब्लू12 और वीर सिंह पीडब्लू13 कथित तौर पर उक्त रिवॉल्वर और मोबाइल हैंडसेट

आरोपी- अपीलकर्ता गजराज सिंह की निशानदेही पर बरामद किया गया था। युवराज ने PW12 के रूप में पेश होते हुए रिकवरी मेमो पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि उनके हस्ताक्षर कोरे कागजों पर लिए गए थे, जिनका उपयोग रिकवरी मेमो तैयार करने में किया गया था। इसी तरह का एक बयान वीर सिंह पीडब्लू13.1 द्वारा दिया गया था, जो धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी- अपीलकर्ता द्वारा दिए गए बयान की ओर इशारा करते हुए प्रस्तुत किया गया था, कि आरोपी- अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा था, कि जांच अधिकारी मामले में, इरादतन और जानबूझकर आरोपी- अपीलकर्ता को फंसाया गया था।

12. हमने आरोपी- अपीलकर्ता के विद्वान वकील के द्वारा किये गए दूसरे निवेदन की जांच की है। युवराज पीडब्लू12 और वीर सिंह पीडब्लू13 के बयान का मूल्यांकन करने से पहले, आरोपी- अपीलकर्ता के साथ उनके संबंधों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जबकि युवराज पीडब्लू12 आरोपी- अपीलकर्ता का भाई है, वीर सिंह पीडब्लू13 उसके पिता हैं। यह स्पष्ट है कि वे आरोपी- अपीलकर्ता को बरी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उपरोक्त के बावजूद, अभियुक्त- अपीलकर्ता के विद्वान वकील के हाथों दी गई दलीलों से यह स्पष्ट है कि न तो युवराज पीडब्लू12 और न ही वीर सिंह पीडब्लू13 ने रिकवरी मेमो पर उनके हस्ताक्षरों की सत्यता पर विवाद किया। इसलिए, यह स्पष्ट है कि रिकवरी मेमो पर उनके हस्ताक्षर प्रामाणिक थे। यदि जांच एजेंसी ने आरोपी- अपीलकर्ता के भाई और पिता

के हस्ताक्षर जबरन ले लिए थे, तो हमारे मन में कोई संदेह नहीं है, कि न केवल आरोपी- अपीलकर्ता बल्कि उसके भाई युवराज पीडब्लू12 और उसके पिता वीर सिंह पीडब्लू13 ने शोर मचा दिया होता। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह बताते हुए अभ्यावेदन दिया होता कि पुलिस ने कोरे कागजों पर उनके हस्ताक्षर लिए थे। युवराज पीडब्लू12 और वीर सिंह पीडब्लू13 के बयानों से उनके द्वारा की गई ऐसी किसी कार्रवाई का पता नहीं चलता है। इसलिए, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है, कि उन्होंने रिकवरी मेमो पर विधिवत अपने हस्ताक्षर किए थे, जिसके माध्यम से मृतक की रिवॉल्वर, साथ ही पैनासोनिक कंपनी का आईईएमआई नंबर 35136304044030 वाला मोबाइल हैंडसेट अभियुक्त-अपीलार्थी गजराज सिंह की निशानदेही पर बरामद किया गया था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें अभियुक्त- अपीलकर्ता की ओर से पेश किए गए दूसरे तर्क में भी कोई योग्यता नहीं मिलती है।

13. आरोपी- अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा पेश किया गया तीसरा और आखिरी तर्क आरोपी- अपीलकर्ता द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, कुंदन नगर शाखा, दिल्ली में अपने खाते में 9,000/- रुपये जमा करने के संबंध में था। अपीलकर्ता- अभियुक्त के विद्वान वकील का यह तर्क था कि मृतक हरीश कुमार की पत्नी मिनाक्षी पीडब्लू 23 ने बताया था कि मृतक के पास 3 लाख रुपये की राशि थी, जब वह चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। . विद्वान वकील के अनुसार, 9,000/- रुपये की जमा

राशि का चित्रण, अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने का एक निरर्थक प्रयास था, कि आरोपी- अपीलकर्ता ने मृतक हरीश कुमार से ली गई धनराशि का एक हिस्सा जमा किया था, ताकि अपराध के साथ उसका सम्बंध स्थापित किया जा सके। यह दावा किया गया कि अभियोजन पक्ष यह नहीं दिखा सका कि आरोपी- अपीलकर्ता ने शेष राशि का निपटान कैसे किया।

14. हमारे लिए तीसरे तर्क को भी स्वीकार करना संभव नहीं है। अभियुक्त- अपीलकर्ता के विद्वान वकील के हाथों विवाद आगे बढ़ा। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि आरोपी द्वारा अपने बैंक खाते में जमा की गई कुल 3 लाख रुपये की राशि में से 9,000/- रुपये की राशि यह स्थापित करने के लिए उचित आधार नहीं हो सकती है कि कथित अपराध आरोपी-अपीलार्थी द्वारा किया गया था। अपीलकर्ता लेकिन फिर, अपराध को स्थापित करने में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए भारी सबूतों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्, अभियुक्त- अपीलकर्ता के कब्जे से मृतक की रिवॉल्वर की बरामदगी, जीवित और इस्तेमाल किए गए कारतूसों के साथ, पैनासोनिक ब्रांड के मोबाइल हैंडसेट की बरामदगी, जिसका आईईएमआई नंबर 35136304044030 है और यह तथ्य कि आरोपी- अपीलकर्ता मृतक हरीश कुमार की हत्या के तुरंत बाद मोबाइल फोन (सिम) नंबर 9818480558 का उपयोग कर रहा था, जो आरोपी- अपीलकर्ता के नाम पर पंजीकृत था। (और वह अपनी गिरफ्तारी तक इसका उपयोग करता रहा), किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है, कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को

साबित किया है जो आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा भी स्थापित पाये गये हैं।

15. यहां ऊपर दर्ज किए गए कारणों से हमें तत्काल अपील में कोई मेरिट नहीं मिलती है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रवि प्रकाश बाकोलिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।